भोपाल | रविवार | 19 अप्रैल 2026 | वर्ष 70 | अंक 86 | पृष्ठ 12 | मूल्य रु.5.00 navabharat.com twitter.com/Nava_Bharat fb.me/NavaBharat.Social

नव भारत
राष्ट्रहित का प्रहरी 1934 से

भगवान परशुराम जयंती की शुभकामनाएं

2 होर्मुज में टोल-निजीकरण मंजूर नहीं

4 एक दिल था सीने में...

10 ज्योतिषीय दूरदर्शन : एक विधा का सृजन और विनाश

11 ईरान युद्ध और भारत की गुप्त कूटनीति

विपक्ष ने नारी शक्ति की उड़ान रोकी

कांग्रेस, टीएमसी, डीएमके जैसे विपक्षी दल भ्रूणहत्या के गुनहगार : मोदी

- प्रधानमंत्री ने देश को 30 मिनट तक संबोधित किया
- बिल में संशोधन नहीं होने पर मांगी माफी

नई दिल्ली, 18 अप्रैल. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार की शाम 8.30 बजे महिला आरक्षण पर देश को संबोधित किया. उन्होंने कहा, इस बिल में संशोधन नहीं हो पाया. मैं सभी माताओं-बहनों से माफी मांगता हूं.

उन्होंने कहा, मेरे लिए देशहित सर्वोपरि है, जब कुछ लोगों के लिए दल हित सब कुछ हो जाता है औ दल हित देश हित से बड़ा हो जाता है. तो नारी शक्ति को ही इसका खामियाजा उठाना पड़ता है.

पीएम ने कहा कि कांग्रेस, टीएमसी, डीएमके जैसे विपक्षी दल इस भ्रूणहत्या के गुनहगार हैं. ये देश के संविधान के अपराधी हैं. नारी शक्ति के अपराधी हैं. जिन लोगों ने आधी आबादी का अधिकार छीना, उन्हें इस पाप की सजा मिलेगी.

कांग्रेस परजीवी की तरह दूसरे दलों के सहारे जिंदा

पीएम ने कहा- कांग्रेस खुद ही कई राज्यों में अपना वजूद खो चुकी है. वह परजीवी की तरह दूसरे दलों के सहारे जिंदा है. वे यह भी नहीं चाहते कि क्षेत्रीय दलों की ताकत बढ़े. इस बिल को रोककर उन्हें राजनीतिक षड्यंत्र किया है. सभी विपक्ष इतने सालों से हर बार वही बहाने बनाते आए हैं. कोई न कोई पेंच फंसाकर महिलाओं के अधिकारों पर डाका डालते हैं. उन्होंने कहा- देश उनका पैटर्न समझ चुका है. इस बिल के विरोध की बढ़ी वजह है कि इन परिवारवादी पार्टियों का डर. इन्हें डर है कि महिला सशक्त हुई तो उनकी पार्टी खतरे में आ जाएगी. ये नहीं चाहेंगे कि उनके परिवार के बाहर की महिलाएं आगे बढ़े.

संबोधन की मुख्य बातें

- **महिलाओं के सपने को कुचल दिया :** आज भारत का हर नागरिक देख रहा है कि कैसे भारत की नारी शक्ति की उड़ान को रोक दिया गया, उनके सपनों को बेरहमी से कुचल दिया गया.
- **विपक्ष ने मेजें थपथपाई :** कांग्रेस, डीएमके, टीएमसी और समाजवादी पार्टी जैसे दलों की स्वार्थी राजनीति का नुकसान देश की नारी शक्ति को उठाना पड़ा है. शुक्रवार को देश की करोड़ों महिलाओं की नजर संसद पर थी. देश की नारी शक्ति देख रही थी. मुझे भी ये देखकर बहुत दुख हुआ कि जब ये नारी हित का प्रस्ताव गिरा तो कांग्रेस, डीएमके, टीएमसी, सपा जैसी परिवारवादी पार्टियां खुशी से तालियां बजा रही थीं. महिलाओं से उनके अधिकार छीनकर ये लोग मेजें थपथपा रहे थे.
- **नारी अपमान नहीं भूलती :** शुक्रवार को विपक्ष ने जो भी किया वह केवल टेबल पर थाप नहीं थी. वह नारी के स्वाभिमान पर उसके आत्म सम्मान पर चोट थी. और नारी सब भूल जाती है, अपना अपमान कभी नहीं भूलती. इसलिए संसद में कांग्रेस के उसके सहयोगियों के व्यवहार की कसक, हर नारी के मन में हमेशा रहेगी. देश की नारी जब भी अपने क्षेत्र में इन नेताओं को देखेगी तो वह याद करेगी कि इन्हीं लोगों ने संसद में महिला आरक्षण को रोकने का जश्न मनाया था, खुशियां मनाईं थीं.
- **विपक्ष को उसके पाप की सजा जरूर मिलेगी :** नारी शक्ति वंदन विधेयक का जिन लोगों ने विरोध किया है, उनसे मैं दो टूक कहूंगा कि ये लोग नारी शक्ति को फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं. वे ये भूल रहे हैं कि 21वीं सदी की नारी देश की हर घटना पर नजर रख रही है. वह उनकी मंशा भांप रही है और सच्चाई भी भली-भांति जान चुकी है. महिला आरक्षण विधेयक का विरोध कर के विपक्ष ने जो पाप किया है, उसकी सजा उन्हें जरूर मिलेगी. इन दलों ने संविधान निर्माता की भावनाओं का भी अपमान किया है. और जनता द्वारा इसकी सजा से भी वे बच नहीं पाएंगे.

होर्मुज में भारतीय जहाज पर फायरिंग

ईरानी गनबोट्स ने चेतावनी दिए बिना किया हमला

विदेश मंत्रालय ने ईरान के राजदूत को किया तलब

तेहरान/नई दिल्ली, 18 अप्रैल. होर्मुज स्ट्रेट से गुजरने की कोशिश कर रहे दो व्यापारी जहाजों पर शनिवार दोपहर गोलीबारी हुई. इसमें एक भारतीय झंडे वाला तेल जहाज भी शामिल था. यह जानकारी कई समुद्री और सुरक्षा सूत्रों ने दी है, जिसे शिपिंग मॉनिटर टैंकर ट्रैकर्स ने रिपोर्ट किया.

ब्रिटेन के समुद्री निगरानी केंद्र मैरिटाइम ट्रेड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक, ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड की दो गनबोट्स टैंकर्स के पास आईं और बिना रेडियो चेतावनी फायरिंग शुरू कर दी. इसके बाद दोनों जहाज स्ट्रेट पार किए बिना ही लौट गए. हालांकि जहाज और उसके क्रू मेंबर सुरक्षित बताए गए हैं. रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय जहाज में लगभग 20 लाख बैरल इराकी तेल था. इजरायल और लेबनान के बीच 10 दिनों के सीजफायर का ऐलान होने के बावजूद हमले नहीं रुके हैं. इजरायली सेना ने दावा किया कि उसने दक्षिणी लेबनान में हवाई और जमीनी हमले किए हैं.

हिज्बुल्लाह के कई ठिकानों पर भीषण अटैक किए. हिजबुल्लाह के वरिष्ठ अधिकारी ने सख्त चेतावनी दी कि संगठन इजरायल की ऐसी किसी भी सैन्य कार्रवाई को बर्दाश्त नहीं करेगा. उन्होंने नवंबर 2024 के युद्धविराम के बाद की स्थिति का जिक्र करते हुए कहा कि उस समय इजरायल ने लगभग रोजाना हवाई हमले जारी रखे थे.

भारत ने सख्त रुख दिखाया

इस घटना के बाद भारत ने सख्त रुख दिखाया है. रिपोर्ट के मुताबिक भारत के विदेश मंत्रालय ने शनिवार को भारत में तैनात ईरान के राजदूत डॉ. मोहम्मद फथअली को तलब किया और इस घटना पर औपचारिक विरोध दर्ज कराया.

24 घंटे के भीतर फिर ईरान ने बंद किया होर्मुज

ईरान ने फिर से स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को बंद करने की घोषणा की है. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की धमकी के बाद ईरान ने ये फैसला लिया है. ईरान की संयुक्त सैन्य कमान ने शनिवार को कहा कि होर्मुज पर उसका नियंत्रण पहले जैसा हो गया है. उसने चेतावनी दी कि जब तक ईरानी बंदरगाहों पर अमेरिकी नाकाबंदी जारी रहेगी, तब तक वह होर्मुज से आवागमन ब्लॉक करना जारी रखेगा.

रेलवे-इंश्योरेंस समेत 5 प्रोजेक्ट्स को हरी झंडी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट

24 815 करोड़ के दो बड़े मल्टी-ट्रैकिंग प्रोजेक्ट्स मंजूर

12 980 करोड़ के 'भारत मैरिटाइम इंश्योरेंस पूल' को मंजूरी

नई दिल्ली, 18 अप्रैल. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट ने शनिवार को 5 प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी.

कैबिनेट ने केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए महंगाई भत्ता (डीए) और महंगाई राहत (डीआर) में 2 प्रतिशत की बढ़ोतरी को मंजूरी दी है. अब यह बढ़कर 58 से 60 प्रतिशत हो गया है, जो 1 जनवरी 2026 से लागू होगा. रेलवे के 24,815 करोड़ रुपए के दो बड़े मल्टी-ट्रैकिंग प्रोजेक्ट्स में गाजियाबाद-सीतापुर और राजमुंदरी-विशाखापट्टनम रूट शामिल हैं. केंद्र सरकार ने बढ़ते वैश्विक तनाव के बीच समुद्री व्यापार को सुरक्षित रखने के लिए 12,980 करोड़ रुपए के 'भारत मैरिटाइम इंश्योरेंस पूल' को मंजूरी दी है. साथ ही प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए 83,977 करोड़ रुपए का ऐलान किया है. केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री अश्वनी वैष्णव ने शनिवार को बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति ने भारतीय रेलवे के दो बड़े मल्टी-ट्रैकिंग प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दे दी है.

इन परियोजनाओं की कुल लागत लगभग 24,815 करोड़ है और इन्हें वर्ष 2030-31 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है. उन्होंने बताया कि इन परियोजनाओं के तहत उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश के कुल 15 जिलों को कवर किया जाएगा, जिससे भारतीय रेलवे नेटवर्क में करीब 601 किलोमीटर की बढ़ोतरी होगी. इन परियोजनाओं से रेलवे की लाइन क्षमता में बड़ा इजाफा होगा, जिससे ट्रेनों की आवाजाही तेज और सुगम होगी. साथ ही, भीड़भाड़ कम होगी और सेवाओं की ...

शेष पेज 7 पर

लोकसभा और राज्यसभा कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित

नई दिल्ली, 18 अप्रैल. लोक सभा के बजट सत्र के शनिवार को समाप्त होने के साथ ही सदन की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई. अध्यक्ष ओम बिरला ने कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित किये जाने से पहले कहा कि 18वीं लोकसभा के सातवें सत्र की 28 जनवरी को शुरुआत हुई थी. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने 28 जनवरी को ही दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित किया था. सत्र में 31 बैठकें हुईं. वहीं राज्यसभा के सभापति सीपी राधाकृष्णन ने संसद के विस्तारित बजट सत्र के संपन्न होने के साथ ही उच्च सदन के 270 वें सत्र की कार्यवाही शनिवार को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी.

चारधाम यात्रा के लिए 18 लाख श्रद्धालुओं ने करवाया रजिस्ट्रेशन

देहरादून. उत्तराखंड में चारधाम यात्रा शुरू चुकी है. ऋषिकेश में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 10 बसों को यमुनोत्री व गंगोत्री धाम के लिए रवाना किया. चारधाम के लिए अब तक 18.25 लाख श्रद्धालुओं ने रजिस्ट्रेशन करवा लिया है. पिछले साल 23 लाख श्रद्धालुओं ने रजिस्ट्रेशन करवाया था. ऋषिकेश और हरिद्वार में ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन काउंटर भी शुरू हो चुके हैं. सबसे पहले मध्य प्रदेश के 100 यात्रियों ने रजिस्ट्रेशन करवाया. ये सभी यमुनोत्री और गंगोत्री के दर्शन करेंगे. बता दें कि बद्रीनाथ-केदारनाथ मंदिर में गैर हिंदुओं के प्रवेश पर रोक रहेगी. हिंदू, बौद्ध, सिख, जैन धर्म के लोग दर्शन कर पाएंगे.

राहुल गांधी के आवास पर प्रदर्शन

बीजेपी की महिला कार्यकर्ताओं ने फूंका पुतला

नई दिल्ली, 18 अप्रैल. महिला आरक्षण बिल पास न हो पाने के बाद देश की राजनीति गरमा गई है. भाजपा ने कांग्रेस और विपक्ष पर जोरदार हमला करते हुए दिल्ली में बड़ा प्रदर्शन किया. कई वरिष्ठ भाजपा नेता और महिला सांसद समर्थकों के साथ कांग्रेस नेता राहुल गांधी के घर तक मार्च करते हुए पहुंचे.

इस प्रदर्शन में हेमा मालिनी और बांसुरी स्वराज समेत कई सांसद शामिल थीं. दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा भी इस मार्च में मौजूद रहे. पार्टी ने सोशल मीडिया पर धोखेबाज लिखे पोस्टर साझा कर विपक्ष पर निशाना साधा और कहा कि देश की आधी आबादी इसे कभी माफ नहीं करेगी.

भाजपा ने इस मुद्दे पर सड़क से लेकर सोशल मीडिया तक अभियान चलाया. प्रदर्शन के दौरान नेताओं ने काले झंडे दिखाए और माथे पर काली पट्टी बांधकर विरोध जताया. उनके हाथों में ऐसे पोस्टर थे, जिनमें विपक्ष पर 'नारी शक्ति' का अपमान करने के आरोप लगाए गए.

राहुल पर एफआईआर मामले में कोर्ट ने अपना आदेश बदला

लखनऊ. इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के खिलाफ दोहरी नागरिकता मामले में एफआईआर दर्ज करने संबंधी अपने ही आदेश को बदल दिया है. कोर्ट ने शनिवार को अपनी वेबसाइट पर संशोधित आदेश जारी किया. शुक्रवार को न्यायमूर्ति सुभाष विद्यार्थी की एकलपीठ ने याचिका की सुनवाई की.

विधेयक दोनों दल इसे अपने-अपने तरीके से राजनीतिक लाभ के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं

दलों के बीच नैरेटिव युद्ध में फंसा महिलाओं का अधिकार

प्रवेश कुमार मिश्र

नई दिल्ली, 18 अप्रैल. महिला आरक्षण विधेयक (नारी शक्ति वंदन अधिनियम) और इससे जुड़ी जनगणना व परिसीमन जैसी जटिल प्रक्रियाओं की भूलभुलैया में फंसा भारतीय महिलाओं का संसद में समान भागीदारी का सपना फिर से फाइलों में दबने के साथ ही भाजपा और कांग्रेस के बीच एक बड़ा नैरेटिव युद्ध छिड़ गया है. दोनों दल इसे अपने-अपने तरीके से राजनीतिक लाभ के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं.

विधेयक के प्रावधानों के अनुसार, महिला आरक्षण जनगणना और उसके बाद होने वाले परिसीमन के बाद ही लागू हो पाएगा. ऐसे में राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह तकनीकी पेंच इस कानून को कम से कम 2029 के लोकसभा चुनावों तक के लिए टाल देगा. हालांकि विपक्ष ने इसे सरकार का चुनावी जुमला करार देते हुए सवाल उठाया है कि यदि सरकार की नीयत साफ थी, तो इसे तत्काल प्रभाव से पहले से पारित बिल को लागू करने में क्या बाधा थी? वहीं, सत्ता पक्ष का तर्क है कि परिसीमन के बिना सीटों का निर्धारण संवैधानिक रूप से चुनौतीपूर्ण और विवादास्पद हो सकता था. जानकार बता रहे हैं कि तर्क-वितर्क और आरोप-प्रत्यारोप के कारण हुई देरी ने राजनीतिक ध्रुवीकरण को और तेज कर दिया है. ओबीसी कोटे के भीतर कोटा की मांग ने इस विमर्श को एक नई दिशा दे दी है. क्षेत्रीय दलों और विपक्षी गठबंधन ने इसे पिछड़ा वर्ग की महिलाओं के हक की लड़ाई बनाकर सरकार की घेराबंदी ...

शेष पेज 7 पर

> बहरहाल, उक्त विधेयक को पारित कराने के लिए जरूरी दो तिहाई बहुमत नहीं होने के बावजूद सरकार द्वारा लाया गया यह संविधान संशोधन विधेयक संख्या बल के कारण गिर तो गया है, लेकिन इसके गर्भ से कई सवालों का जन्म भी हुआ है. लगभग बारह वर्षों में पहली बार सरकार को मिली चुनौती से जहां उसे आत्ममंथन करने का मौका मिला है. वहीं लगातार बिखरती विपक्षी एकता को एक बार फिर एकजुटता दिखाने का मौका दे दिया है.